LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi Sunita Arora Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka) No. 3, Wednesday, July 20, 2022/Ashadha 29, 1944 (Saka)

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 41	10-16
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 42 to 60	17-69
Unstarred Question Nos. 461 to 690	70-709

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPER	S LAID ON THE TABLE	710-714, 716
ASSEN	T TO BILLS	715
	ACCOUNTS COMMITTEE 1 st and 52 nd Reports	717
STATE	MENTS BY MINISTERS	718-719
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 357 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021- 22) pertaining to the Ministry of Earth Sciences Dr. Jitendra Singh	718
(ii)(a) (b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 11 th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on 'Price Rise of Essential Commodities – Causes and Effects' pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Status of implementation of the recommendations contained in the 19 th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Consumer Affairs,	
	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	
	Shri Arjun Ram Meghwal	719

	ION RE: 34 TH REPORT OF THE BUSINESS ISORY COMMITTEE	720
MAT	TERS UNDER RULE 377	721-748
(i)	Need to provide lift irrigation facility in Gujarat particularly in Rajkot and Morbi districts	
	Shri Mohanbhai Kundariya	721-722
(ii)	Regarding condition of schools in Chhattisgarh.	
	Shri Mohan Mandavi	723
(iii)	Regarding construction of Ramganjmandi- Bhopal railway line	
	Shri Rodmal Nagar	724
(iv)	Regarding converting NH - 351 in Gujarat into four lane road	
	Shri Naranbhai Kachhadiya	725
(v)	Need to construct a pit line at Latur Railway Station	
	Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	726
(vi)	Regarding expansion of Kishangarh airport in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Bhagirath Choudhary	727

(vii)	Regarding conversion of NH 28 from	
	Mazaffarpur to Barauni into four- lane	
	Shri Ajay Nishad	728
(viii)	Regarding scheduled tribe status to Lohara caste in Bihar	
	Shrimati Rama Devi	729
(ix)	Regarding setting up of Integrated Manufacturing Cluster in Garhwa district, Jharkhand	
	Shri Vishnu Dayal Ram	730
(x)	Need to upgrade schools in Maharajganj Parliamentary Constituency in Bihar as PM Shri Schools	
	Shri Janardan Singh Sigriwal	731
(xi)	Regarding payment of claims to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Mahasamund Parliamentary Constituency, Chhattisgarh	
	Shri Chunnilal Sahu	732

(xii)	Need to set up a sports stadium of international standard in Lohardaga district, Jharkhand	
	Shri Sudarshan Bhagat	733
(xiii)	Regarding release of arrears of payments to hospitals under Ayushman Bharat Yojana in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand	
	Shri Bidyut Baran Mahato	734-735
(xiv)	Need to provide stoppage of Shivganga Express at Gyanpur Road railway station in Uttar Pradesh	
	Shri Ramesh Bind	735-736
(xv)	Regarding introduction of air conditioned rail ambulance	
	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	737
(xvi)	Regarding setting up of an airport at Chengannur in Mavelikkara Parliamentary Constituency	
	Shri Kodikunnil Suresh	738
(xvii)	Regarding construction of a bridge over river Bhavani in Palakkad district, Kerala	
	Shri V. K. Sreekandan	739

(xviii)	Regarding plight of traditional indian fishermen	
	Shri T. N. Prathapan	740
(xix)	Need to operate a regular reserved train between Coimbatore/Mettupalayam and South Tamil Nadu	
	Shri P. Velusamy	741
(xx)	Regarding RINL tender relating to coke oven batteries	
	Shri Margani Bharat	742
(xxi)	Regarding promoting export of agricultural products	
	Shri Pocha Brahmananda Reddy	743
(xxii)	Need to develop sports infrastructure and facilities under 'Khelo India Yojana' in Goplaganj district, Bihar	
	Dr. Alok Kumar Suman	744
(xxiii)	Regarding payment of arrears of honorarium to Madrasa teachers and also increase the amount of honorarium being paid to them	
	Kunwar Danish Ali	745-746
(xxiv)	Regarding merger of schools in Andhra Pradesh	
	Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	747

(xxv) Regarding sanctioning of a Central Agriculture University in Tamil Nadu

Shri P. Ravindhranath	748
*ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	737
Member-wise Index to Unstarred Questions	738-744
*ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	745
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	746

^{*} Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES	

LOK SABHA

Wednesday, July 20, 2022/Ashadha 29, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 41 – श्री चुन्नीलाल साहू।

... (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

(Q. 41)

श्री चुन्नीलाल साहू: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में खाद्य निगम के वर्तमान में कितने गोदाम हैं? इन गोदामों में इनकी क्षमता से अधिक खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? ... (व्यवधान)

क्या छत्तीसगढ़ में नए गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा सरकार के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो इनके निर्माण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब बैठ जाइये। T. R. Baalu ji, every time, I allow you.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराये की... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप आसन की बात नहीं मानेंगे तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। जब मैंने आपको कहा कि मैं प्रश्न काल के बाद आपको इजाजत दूंगा। आप अपनी सीट पर बैठिये।

... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : भंडारण क्षमता अच्छी है और भंडारण की व्यवस्था अच्छी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यहां विषय मत रखो। इसकी अनुमित नहीं दी गई है। मैंने आपको कहा कि मैं क्वेश्वन ऑवर के बाद अलाऊ करूंगा।

... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : सरकार वेयरहाउस को किराये पर लेती है। भंडारण क्षमता की कमी नहीं है।... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल साहू: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: एक बार गोदामों के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं।... (व्यवधान) महासमुन्द जिले के दूरस्थ अंचल सीमावर्ती क्षेत्र सरायपाली, बसना में क्या एफसीआई स्वयं का अपना गोदाम बनाएगी? इसके लिए मैं मांग करता हूं और साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्रों से महाराष्ट्र में चावल जाता है, जिसमें तीन बार परिवहन होता है।... (व्यवधान) एक बार सड़क मार्ग से, फिर रेल मार्ग से तथा फिर सड़क मार्ग से परिवहन होता है। तीन बार परिवहन होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता कम होती है तथा भाड़ा भी ज्यादा लगता है।... (व्यवधान) मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क मार्ग के माध्यम से ही एक बार परिवहन की व्यवस्था की जाए।... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भंडारण की क्षमता पर्याप्त है। राज्य सरकार और भारत सरकार के गोदामों की वहां कमी नहीं है। जितनी उपज होती है, उससे अधिक भंडारण की क्षमता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। मैं आपको चर्चा करने के लिए प्रश्न काल के बाद शून्य काल में अलाऊ करूँगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री जी यहां पर

बैठे हैं और विरष्ठ मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। नारेबाजी और तिख्तयों के लिए नहीं है। आप सदन की गिरमा को गिरा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काल अमृत काल खंड चल रहा है। आप चर्चा करें, संवाद करें, सहमित करें, असहमित करें और आलोचना करें। मैं सब को अलाऊ करूँगा।

लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रश्न काल के बाद मैं आपको शून्य काल के अंदर अलाऊ करूंगा। आपका यह रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुन: आग्रह करूंगा। उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको प्रश्न काल के बाद शून्य काल के अंदर बोलने की अनुमित दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहां पर बैठे हैं। अगर आप सीट पर जा कर बैठते हैं तो मैं आपको अलाऊ करूंगा। अगर आप सीट पर जा कर नहीं बैठते हैं तो मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जब आप इतने बड़े दिल से यह कह रहे हैं कि सबको अलाऊ करूंगा, चर्चा करवाऊंगा, फिर भी ये लोग वेल में आ कर बाधा डाल रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) सर, हम वर्ष में तीन-चार बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपीज़ यह चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्वन ऑवर चलाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) उस तरफ के भी कुछ लोग क्वेश्वन ऑवर चलाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) इन लोगों का चर्चा करने का इरादा है या नहीं, यह कांग्रेस पार्टी और उनके ईको सिस्टम के जो फ्रेन्ड्स हैं, वे स्पष्ट करें। ... (व्यवधान) सर, मैं यह आग्रह करता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सिंहत देश में एफसीआई के भण्डारण के लिए उन्होंने खुद के गोदाम बनाए हुए हैं। ... (व्यवधान) लेकिन देखने में आता है कि पूरे देश में एफसीआई जिन गोदामों में अनुबंध के माध्यम से भण्डारण करती है और जो एफसीआई के स्वयं के गोदाम हैं, तो जो हानि होती है, क्षित होती है, स्वयं के जहां भण्डारण होते हैं, जहां एफसीआई के अपने कर्मचारी देख-रेख करते हैं, वहां ज्यादा क्षित होती है। ... (व्यवधान) जहां पर अनुबंध के

आधार पर भण्डारण किया जाता है, वहां पर क्षित कम होती है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आगे आने वाले समय में, ऐसी कोई योजना जिसमें एफसीआई को कम से कम हानि हो, क्या उस दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ेगा? ... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश से जुड़ा और पूरे देश से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। ... (व्यवधान) कुल भण्डारण क्षमता स्वयं की और किराए की 413 लाख मीट्रिक टन है। ... (व्यवधान) राज्य एजेंसियों के पास 362 लाख 77 हज़ार मीट्रिक टन है। ... (व्यवधान) महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2014 के बाद से कहीं भी अन्न खराब नहीं हुआ है। ... (व्यवधान) वर्ष 2020 से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण पैकेज लागू कर के साधारण व्यक्ति को ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ... (व्यवधान) कहीं भी अन्न की बर्बादी नहीं हो रही है। ... (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र माझी: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ओडिशा में कितने एफसीआई गोदाम हैं? ... (व्यवधान) इसकी कैपेसिटी क्या है? ... (व्यवधान) नए गोदाम खोलने के लिए कितने प्रपोजल ओडिशा से आए हैं? ... (व्यवधान) नए गोदामों के लिए बजट कॉस्ट क्या है? ... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लिए मैंने अभी आपको बताया था, ओडिशा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ... (व्यवधान) पूरे देश के लिए सतत् प्रक्रिया है और ओडिशा में अपने गोदाम केवल 565 हैं और किराए पर 1552 हैं। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, गोदामों की कमी नहीं है। ... (व्यवधान) गोदामों की व्यवस्था हमारी सरकार लगातार कर रही है। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य के सामने विषय जरूर रखना चाहती हूँ और जो ये साथ में खड़े हैं, मैं उनको भी एक संकेत देना चाहती हूँ। ... (व्यवधान) अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गेहूं और चावल बर्बाद हो रहा है। ... (व्यवधान) यदि मैं वर्ष 2014 के पहले जाऊं तब कितना बर्बाद होता था, ये आंकड़े मैं प्रस्तुत कर सकती हूं। ... (व्यवधान) आज कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ...

(व्यवधान) हाँ, कहीं बरसात के कारण या बाढ़ आने के कारण हो सकता है। ... (व्यवधान) बाकी कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ... (व्यवधान)

श्री जगदिम्बका पाल: अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। ... (व्यवधान) पूरे देश के उत्पादन का यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना में हमने पिछले दो वर्षों से देश के 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान मुफ्त राशन दिया है। ...(व्यवधान) देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रखने की कठिनाई भी है। ...(व्यवधान)

इस पर एफसीआई काम भी कर रही है। ...(व्यवधान) इस दौरान उत्तर प्रदेश से साइलो बनाने की मांग हो रही है। माननीय विषठ मंत्री जी मौजूद हैं। ... (व्यवधान) पूरे देश में एफसीआई के जो मौजूदा गोदाम हैं, उनकी जगह पर अब साइलो गोदाम बन रहे हैं। ...(व्यवधान) उसकी जो मांग उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में है, उसकी क्या नीति है और क्या उत्तर प्रदेश में साइलो गोदामों की और स्वीकृतियां जारी करेंगे? यह मैं जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलो में सिर्फ गेहूँ रखा जाता है, चावल नहीं रखा जाता।... (व्यवधान) जहां जरूरत है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी इसकी स्वीकृति हुई है।... (व्यवधान) चावल और गेहूँ, दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है, इसलिए चावल कभी साइलो में नहीं रखा जा सकता।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं उन्हें पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पीयूष गोयल जी।

... (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।...

(व्यवधान) वास्तव में, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद देश भर में ऐसी व्यापक व्यवस्था की जा रही है, जिससे अनाज को बड़ी एफिशिएंटली हैण्डल किया जा सके, अनाज को बहुत अच्छे तरीके से वितरित किया जा सके।... (व्यवधान) पूरे सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इसके लिए रेल मंत्रालय, एफ.सी.आई., सी.डब्ल्यू.सी. और अन्य जो सरकारी विभाग हैं, उनके साथ-साथ कई राज्य सरकारों की मदद से हमने आज देश में 249 साइलोज़, जिनकी कुल क्षमता 111 लाख मीट्रिक टन होगी, इसका काम प्रारम्भ कर दिया है।... (व्यवधान) हर एक प्रदेश में, जहां-जहां आवश्यकता दिखी, वहां पर ये साइलोज़ आ रहे हैं।... (व्यवधान) ये 'हब एण्ड स्पोक' मॉडल में आ रहे हैं, जिससे एक ज़गह पर बड़े पैमाने पर गेहूँ को लाया जाएगा और फिर छोटे-छोटे इलाकों में, क्षेत्रों में, स्पोक्स के माध्यम से यह गेहूँ लोकल उपलब्ध होगा... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश की बात की गई, तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, रामपुर, जालौन, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आज़मगढ़, बिलया, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, भदोही, मेरठ, अमेठी, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, फर्रुखाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, झाँसी, सिद्धार्थनगर, कानपुर, सम्भल, चन्दौली, बदायूँ, बांदा और उन्नाव, इतने सारे क्षेत्रों में गेहूँ के साइलोज़ आ रहे हैं।... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की जनता ने एतिहासिक प्यार योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को दिया है, मैं समझता हूं कि सरकार भी दिन-रात सेवा में लगी है, जनता की सेवा में लगी है।... (व्यवधान)

एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूँ के साइलोज़ का इतना बड़ा जाल, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।... (व्यवधान)

मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का जो काम मोदी जी ने शुरू किया है, उस काम को योगी जी दिन-रात आगे बढ़ा रहे हैं।... (व्यवधान) इसका एक प्रमाण जनता के सामने रखा गया है।... (व्यवधान)

धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सदन में चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिस विषय पर आप नारेबाजी कर रहे हैं, यह अच्छी बात है कि मैं आप सबको शून्य काल के अन्दर इसके लिए परमिशन दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। शून्य काल के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात चर्चा से देश की जनता के सामने पहुंचाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो यह सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए और लोगों की भावनाओं को उठाने के लिए है। आप प्रश्न काल जैसे महत्वपूर्ण समय में नारेबाजी करते हैं, तख्तियाँ लहराते हैं। यह सदन के लिए उचित नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देश की जनता चाहती है कि सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो। सहमित-असहमित इस लोकतंत्र की विशेषता है। अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। यहाँ सदन में नारेबाजी करने के लिए आपको नहीं भेजा है। यहाँ सदन में तख्तियाँ लाने के लिए आपको नहीं भेजा है। संसद का बहुत महत्वपूर्ण समय है और आप हमेशा नारेबाजी करते हैं। यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos.42 to 60
Unstarred Question Nos.461 to 690)
(Page No.17 to709)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

^{*} Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at one minute past Fourteen of the Clock.

(Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)

At this stage, Adv. Dean Kuriakose, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

14.01½hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid.

Item no. 2. Shri Arjun Ram Meghwal.

... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) का.आ. 1004(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी एचएस 0106 90 00 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (2) का.आ. 1145(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।
- (3) का.आ. 1463(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द दाल (एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हिप्पर की फलियां) [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 3110] और तूर/अरहर [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 60 00] (केजैनस कजान) की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

- (4) का.आ. 1559(अ) जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (5) का.आ. 2031(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत आईटीसी (एचएस) कोड 71123000, 71129100, 71129200, 71129910, 71129920 और 71129990 की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (6) का.आ. 2053(अ) जो 02 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 के अंतर्गत उपबंधों की छूट को विस्तारित किये जाने के बारे में है।
- (7) का.आ. 2320(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत ताजा अदरक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (8) का.आ. 2357(अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (9) का.आ. 2378(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 में नीति शर्त के

- समावेश और कागज की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (10) का.आ. 2821(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के अंतर्गत तरबूज बीजों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (11) का.आ. 1549(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध थी, का विस्तार 30 सितम्बर 2022 तक करने के बारे में है।
- (12) का.आ. 1269(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अनुसूची-दो अध्याय-10 क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (13) का.आ. 1270(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2018 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत निर्यात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।
- (14) का.आ. 2162(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (15) का.आ. 2235(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (16) का.आ. 2236(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (17) का.आ. 2321(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांस चारकोल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(18) का.आ. 2375(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीनी की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(19) का.आ. 2985(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची दो के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है। [Placed in Library, See No. LT 7144/17/22]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

- The Aadhaar (Authentication and Offline Verification) (First Amendment) Regulations, 2022 (No. 01 of 2022) published in Notification No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022) in Gazette of India dated 4th February, 2022.
- 2. The Aadhaar (Enrolment and Update) (Ninth Amendment)
 Regulations, 2022 (No. 2 of 2022) published in Notification No.
 HQ-16041/4/2021-EU-I-HQ-Part(I)(No.2 of 2022) in Gazette of India dated 3rd March, 2022.

3. The Aadhaar (Appointment of Officers and Employees) (Second Amendment) Regulations, 2022 (No. 3 of 2022) published in Notification No. F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No.3 of 2022) in Gazette of India dated 21st March, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7145/17/22] ... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.402(E) in Gazette of India dated 30th May, 2022 under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

[Placed in Library, See No. LT 7146/17/22]

(2) A copy of the Low Power Radio Frequency Devices in the frequency band 433.05 to 434.79 MHz (Exemption from License) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.347(E) in Gazette of India dated 11th May, 2022, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 and sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.

[Placed in Library, See No. LT 7147/17/22]

... (Interruptions)

14.03 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY GENERAL: Sir, I lay on the Table the following seven Bills passed by the Houses of Parliament During the Eighth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd February, 2022:-

- 1. The Appropriation (No.2) Bill, 2022;
- 2. The Appropriation (No.3) Bill, 2022;
- 3. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022;
- 4. The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022;
- 5. The Finance Bill, 2022;
- 6. The Appropriation Bill, 2022; and
- 7. The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2022.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of the following four Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

- 1. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022;
- 2. The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022;
- 3. The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022; and
- The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022.

... (Interruptions)

14.04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE - Contd.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) अधिसूचना संख्या 17/2022 केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) अधिसूचना संख्या 18/2022 केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन प्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) अधिसूचना संख्या 19/2022 केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं, नामत: पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से निर्यात किए जाने पर सड़क और अवसंरचना उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) अधिसूचना संख्या 20/2022 केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

14.041/2hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

51st and 52nd Reports

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2022-23):-

- (1) Fifty-first Report on 'Assessment of Assesses in Entertainment Sector (DT)'.
- (2) Fifty-second Report on 'Construction and utilization of Limited Height Subway (LHS)'.

... (Interruptions)

14.05 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 357th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 357th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

... (Interruptions)

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7141/17/22.

14.06 hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on 'Price Rise of Essential Commodities - Causes and Effects' pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my colleague, Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on 'Price Rise of Essential Commodities - Causes and Effects' pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my colleague, Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

 $[^]st$ Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7142/17/22 and 7143/17/22 respectively.

14.07 hrs

MOTION RE: 34TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my senior colleague, Shri

Pralhad Joshi, I beg to move the following:-

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July, 2022."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July, 2022."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

14.07 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Matters under Rule 377.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohanbhai Kundariya to raise his matter.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is not proper.

... (Interruptions)

(i) Need to provide lift irrigation facility in Gujarat particularly in Rajkot and Morbi Districts

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): आदरणीय सभापित महोदय, आप के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान नहर सिंचाई (बांध) की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। राजकोट और मोरबी जिलों सिहत पूरे गुजरात में नहर सिंचाई (बांध) के स्वरुप में खेती के लिए जल आपूर्ति की जाती है। ... (व्यवधान) अगर जल की आपूर्ति प्रधान मंत्री सिचाई योजना के अंतर्गत लिफ्ट इरीगेशन में कन्वर्ट की जाये तो ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के लिए उपयोग में लायी जा सकती है और किसानों की आय में बढोत्तरी एवं फसल के उत्पादन में मददगार साबित हो सकती है।

अतः मैं आप के द्वारा किसान हितैषी नहर सिंचाई (बांध) को लिफ्ट इरीगेशन में जल्दी से जल्दी परिवर्तित करने का निर्देश माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा देने की मांग करता हूँ।

(ii) Regarding condition of Schools in Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): माननीय सभापित महोदय, कांकेर जिले के प्रत्येक विकास खंड में पूर्व राष्ट्रपित डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इगनाईट अंग्रेज़ी माध्यम के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में यदि कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंड के दर्ज आंकडे प्रस्तुत करें तो 1685 है। ... (व्यवधान)

इसी प्रकार छतीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिलों के विकास खंडों में संचालित प्राथिमक एवं माध्यिमक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की लगभग दर्ज संख्या 65000 है। लेकिन चार वर्ष पहले खुले अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों के लिए न विद्यालय भवन है, न ही जगह है, ना शिक्षक और ना ही अधोसंरचना विकास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई पहल की जा रही है। वर्तमान में इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ... (व्यवधान)

दूसरी ओर छतीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाने पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उक्त स्कूलों के प्रति शासन-प्रशासन उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि पूरे राज्य के विकास खंडों मे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इगनाईट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षक, भवन एवं शौचालय तथा आवश्यक अद्योसंरचना का विकास किया जाए, जिससे गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त हो सके।

(iii) Regarding construction of Ramganjmandi-Bhopal railway line

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): माननीय सभापित जी, भारत सरकार द्वारा रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना, रामगंजमंडी-भोपाल जी 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक लाकर बंद कर दी गई थी जिसे 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ कर फास्टट्रैक में शामिल किया गया है। विभागीय उदासीनता के कारण रामगंज मंडी परियोजना का कार्य धीमी गित से चल रहा है। अत: माननीय रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपया इसे गित देकर शीघ्राति शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

(iv) Regarding converting NH-351 in Gujarat into four lane road

श्री नारणभाई काछिड़या (अमरेली): माननीय सभापित जी, आपका ध्यान केन्द्रित करते हुए बताना है कि नेशनल हाईवे NH-351 महुवा-सावरकुंडला-अमरेली-विडया-जेतपुर जो कि 2015 में प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया था उसका काम बहुत धीमी गित से चल रहा है। उसका अलाईमेंट फरवरी 2019 में फाइनल हुआ जिसको एनएचएआई के अनुसार ट्रैफिक कम होने की वजह से उनको फॉर लेन में तब्दील करने के लिए रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मैंने अधीक्षक इंजीनियर के साथ मीटिंग की और उनको ये समस्या बताई तो उनकी ओर से 9, 10 और 11 नवम्बर 2021 को वापस ट्रैफिक सर्वे किया गया जिसमें अमरेली और सावरकुंडला के बीच 1200 पिसियू से ज्यादा ट्रैफिक आया था उसको देखते ये ट्रैफिक फोर लेन का मालूम पड़ता है। उससे पहले जो ट्रैफिक सर्वे करवाया था वो लॉकडाउन की वजह से कम आया था इसलिए उनको रिजेक्ट किया था। परन्तु फरवरी और मार्च 2021 की अगर रिपोर्ट देखें तो ये ट्रैफिक फोर लेन का लगता है। दूसरा, अभी हाल में जो रोड है वो 10 मीटर की ही है और अभी जो वार्षिक योजना की घोषणा हुई उसमें भी ये रोड 10 मीटर की ही बन रही है। महोदय ज्ञात है यह रोड पूरे जिले की एक मात्र रोड है जो गुजरात के पिपावाव पोर्ट को जोड़ती है और भी कई जीआईडीसी है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस रोड को नए रूप से 45 मीटर जमीन अधिग्रहण कर के फोर लेन बनाया जाए क्योंकि ये अमरेली जिला का एक मात्र नेशनल हाईवे है और इसका ट्रैफिक भी ज्यादा है। अभी जो घोषणा हुई है इसमें सिर्फ पैसा खर्च होगा ट्रैफिक का सुधार नहीं होगा। इस रोड को जनहित में और अगले समय को ध्यान में रख के बनाया जाए जिससे पैसे की बर्बादी ना हो और लोगों को सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति: श्री रमेश बिन्द

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एस. मुनिस्वामी

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बिद्युत बरन महतो

... (व्यवधान)

(v) Need to construct a pit line at Latur Railway Station.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): माननीय सभापित जी, लातूर स्टेशन पर पिटलाइन बनाने की मांग बहुत पुरानी है पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण विगत 70 साल से यहां पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है।

लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइ- के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ना संभव हो जाएगा।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री स्विधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats. These are very important issues.

... (Interruptions)

(vi) Regarding expansion of Kishangarh Airport in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर, राजस्थान में स्थित किशनगढ़ हवाईअड़े से वर्तमान में दिल्ली-अहमदाबाद-हैदराबाद-इन्दौर-सूरत एवं मुम्बई की नियमित हवाई सेवायें चल रही हैं। लेकिन, देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिये नियमित उड़ानें प्रारम्भ नहीं होने से एयरपोर्ट का समग्र उपयोग नहीं हो पा रहा, जबिक उक्त एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के चलते एयरपोर्ट के रनवे एंव टर्मिनल विस्तार की कवायद विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। लेकिन, रनवे विस्तार कार्य में ग्राम टूकड़ा की 02 पहाड़ियों की चोटियों की कटाई एव ग्राम गगवाना में स्थित प्रसार भारती के आकाशवाणी टॉवर की ऊंचाई कम करने अथवा अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि उक्त दोनों ही अड़चनों को दूर करने के लिये एयरपोर्ट ओथोरिटी एवं राज्य सरकार के द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण के साथसाथ दो बार प्रशासनिक स्तर पर सर्वे भी कराया जा चुका है और वर्तमान में उक्त दोनों पहाड़ियों की कटाई के लिये वन-विभाग की एन.ओ.सी एवं आकाशवाणी के टॉवर के स्थानान्तरण की पत्रावली विभागीय स्तर पर स्वीकृति हेत् विचाराधीन है।

अतः व्यापक जनिहत को दृष्टिगत रखते हुये किशनगढ़-अजमेर एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही उक्त दोनों बाधाओं को दूर कराकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र सकारात्मक विभागीय कार्यवाही करायी जाये तो इस परियोजना पर हुआ करोड़ों रुपयों का निवेश बहुउपयोगी साबित होगा।

HON. CHAIRPERSON: Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil – Not Present ... (*Interruptions*)

(vii) Regarding conversion of NH-28 from Mazaffarpur to Barauni into four-lane

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से होते हुए बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 को फोर लेन में तब्दील करने की आवश्यकता है।

महोदय, यह सड़क माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरीराज सिंह जी के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के फोर लेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों के समग्र विकास को गित मिलेगी। उक्त राजमार्ग को फोर लेन में तब्दील करने की चिर प्रतीक्षित मांग से माननीय सड़क परिवहन एवम् राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व्यक्तिगत तौर से अवगत हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुजफ्फरपुर के एक सभा में मेरी मांग पर मंच से हजारों लोगों की उपस्थित में इसको फोर लेन में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी इस संबंध में उठाए गए सकारात्मक कदम की चर्चा के अलावा भौतिक रूप में कुछ भी काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में जब माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हम सड़क के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश को नाज हो रहा है। ऐसे में जमीन पर कोई कार्य दिखाई नहीं देने से आम जनों में आक्रोश व्याप्त है।

आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जनहित में यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के कार्यारंभ की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए।

(viii) Regarding scheduled tribe status to Lohara caste in Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापित महोदय, मैं सदन का ध्यान लोहार समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सन् 1950 ई. में रोमन लिपी में Lohara जाित को अनुसूचित जनजाित के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिस तरह से केरल को Kerala, कर्नाटक को Karnataka, योग को Yoga इत्यादि लिखा जाता है, इसी तर्ज पर लोहार को संविधान में Lohara लिखा गया। लेिकन सन् 2006 में संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 के द्वारा Lohara का हिन्दी रूपांतरण लोहारा कर दिया गया, जिसके कारण लोहार समाज को मिलने वाला अनुसूचित जनजाित का अधिकार छिन गया। क्योंिक बिहार में लोहारा और लोहरा नाम की कोई जाित निवास नहीं करती है। ऐसी परिस्थित में लोहार समाज के लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। बिहार में लोहारा या लोहरा जाित नहीं पाई जाती है और न ही लोहारा, लोहरा के निवास, जनसंख्या एवं भूमि संबंधित दस्तावेज ही बिहार सरकार के पास उपलब्ध है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 को रद्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे कि लोहार (Lohara) जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति के रूप में खोया हुआ अधिकार मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Riti Pathak - Not present.

(ix) Regarding setting up of Integrated Manufacturing cluster in Garhwa district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलाम्) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में सेल के 1,180 हेक्टेयर भूमि पर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDC) के तहत (Amritsar-Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में (NICDC) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, भारत सरकार, श्री अमृत लाल मीना ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना के संबंध में 6 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा था। विदित है कि उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा ने उक्त बिन्दुओं पर झारखंड सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना से झारखंड राज्य के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन संभावित है एवं राज्य का संतुलित विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा एवं उद्योग के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे गढ़वा जिला आकांक्षी जिलों की सूची से बाहर निकल सकेगा एवं राज्य के अन्य विकसित जिलों में आ खड़ा होगा। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना हेत् अग्रतर कार्रवाई कराने की कृपा की जाए।

... (व्यवधान)

(x) Need to upgrade schools in Maharajganj Parliamentary Constituency in Bihar as PM Shri Schools

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत सारण प्रमंडल के जिला-सारण (छपरा) एवं जिला-सिवान में परिसीमित मेरा लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज है। इसी प्रमंडल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, देश को दूसरी आजादी दिलाने वाले लोकतंत्र के रक्षक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं महान शिक्षाविद मौलाना मजहरूल हक की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रहा है। ऐसे महान विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली तथा मेरे लोक सभा की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। बिहार तो वैसे ही अति पिछड़ा राज्य है, उसमें भी मेरा लोक सभा क्षेत्र हर क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल एवं क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धित को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2024 तक देश के सभी प्रखंडों में "PM-श्रीस्कूल के नाम से आदर्श" स्कूलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही लाभकारी एवं जनहितकारी योजना है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इस योजना के तहत मेरे लोक सभा के क्षेत्र के सभी प्रखंडों जैसे-पानापुर, तरैयां, मशरक, बनियापुर, लहलादपुर (जनताबाजार), एकमा, मांझी, जलालपुर, भगवानपुर हाट, महराजगंज, बसंतपुर, लकड़ीनवीगंज एवं गोरेयाकोठी में से एक-एक विद्यालय को चयनित कर उक्त योजना के तहत अपग्रेड किया जाए। अत: माननीय सभापति महोदय के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में "PM-श्री" स्कूल उन्नयन हेत् आवश्यक कदम उठाया जाए, जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने में सरकार का सराहनीय सहयोग मिल सके।

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

(xi) Regarding payment of claims to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Mahasamund Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साह (महासमुन्द): महोदय, देश की कृषि ज्यादातर मौसम पर निर्भर करती है।... (व्यवधान) अनेकों बार किसानों की फसल अल्प वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है और किसान कृषि कार्य करने में निःसहाय हो जाते हैं।... (व्यवधान) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' वर्ष 2016 में लागू कर किसानों को राहत देने का कार्य किया गया है, लेकिन इसमें भी राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित ग्रामों में किसानों को प्रधानमंत्री फराल बीमा की राशि को समय पर नहीं देना कृषि कार्य को कमजोर करना है।... (व्यवधान) किसानों के लिए यह एक अभिशाप ही है। महोदय जी, छत्तीसगढ़ में मेरे लोकसभा महासम्ंद क्षेत्रांतर्गत कृषकों को पिछली फसल के समय जिन ग्रामों में अल्प वर्षा के कारण फसल नहीं हुई है, अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने के कारण किसान काफी आक्रोशित हैं, जिन्हें वर्तमान में कृषि के लिए बीज, खाद्य एवं कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने की अति आवश्यकता है।... (व्यवधान) वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर किसान कृषि कार्य से पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण किसान आज योजना से वंचित होकर खुद ठगा सा महसूस कर रहा है।... (व्यवधान) अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अतिशीघ्र प्रदान कराने हेत् निर्देशित करें, ताकि किसानों को अपने कृषि कार्य करने में उक्त योजना का लाभ समय पर मिल सके।... (व्यवधान)

(xii) Need to set up a sports stadium of international standard in Lohardaga district, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय सभापति जी, जैसा कि आपको विदित है, मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा (झारखंड) जनजाति बहुल, ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है।... (व्यवधान) यह आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास जारी है। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान यहां के युवाओं की खेल प्रतिभा की ओर आकर्षित करना चाहुँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गुमला एवं लोहरदगा जिलों के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में देश का मान बढ़ा चुके हैं।... (व्यवधान) आज भी अनेक राष्ट्रीय टीमों में यहाँ के युवक-युवतियाँ खेल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में फुटबाल, हॉकी, एथलेटिक्स आदि खेलों का परंपरागत रूप से प्रचलन हैं। विशेष कर बेटियों की बात करूँ तो उन्होंने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल की अपार प्रतिभाओं से संपन्न यहाँ के युवा आधुनिक खेल परिसरों के अभाव में अभ्यास करते हैं।... (व्यवधान) इन्हें यदि उचित वातावरण और अत्याधुनिक खेल परिसर एवँ प्रशिक्षण मिल जाए तो हमारे क्षेत्र के खिलाडी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा ओलंपिक सहित अन्य खेलों में देश का मान बढा सकेंगे। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए।... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि लोहरदगा जिले में स्टेडियम के निर्माण कर देश के जनजाति बहुल, ग्रामीण अंचल के खिलाडियों का उत्साह एवं मनोबल को बढाने एवं यहाँ के प्रतिभावान खिलाडियों के लिए अवसरों का सृजन करने में केंद्र सरकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाए। मुझे विश्वास है, देश के युवाओं के प्रेरक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, हमारी सरकार लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर देश के समस्त जनजाति अंचलों को उपहार देकर अनुग्रहीत करेगी।... (व्यवधान) इससे अनेकों अभावों में अपना कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। धन्यवाद।... (व्यवधान)

(xiii) Regarding release of arrears of payments to hospitals under Ayushman Bharat Yojana in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय सभापित महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब, वंचित, बीमारियों से पीड़ित परिवारों को उक्त योजना का लाभ मिला है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और गरीबों के प्रति समर्पण को प्रतिबिंबित करता है।

महोदय, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे अस्पताल हैं, जिनका करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण इन अस्पतालों में गरीबों का इलाज होना बंद हो गया है। ऐसे अस्पताल निम्नलिखित हैं:

- 1. मेरिक्सी अपरोक्स
- 2. ब्रह्मनंदा हॉस्पिटल, सरायकेला
- 3. मेडिटिरिना हॉस्पिटल, सरायकेला
- 4. गंगा मेमोरियल, जमशेदपुर
- 5. दया हॉस्पिटल, जमशेदपुर
- 6. अपूर्वा ईशान, जमशेदपुर
- 7. साकेत हॉस्पिटल, जमशेदपुर
- 8. डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड, जमशेदपुर
- 9. मेहरबाई टाटा, जमशेदपुर
- 10. डॉक्टर डी. मिश्रा यूरोलॉजी, जमशेदपुर

अतः, महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत बकाया राशि

का भुगतान कराने की कृपा की जाए, ताकि इन अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों का समुचित इलाज हो सके।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The House cannot run like this.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your Members also have

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Rest of the Members may lay their Matters* on the Table of the House.

(xiv) Need to provide stoppage of Shivganga Express at Gyanpur Road railway station in Uttar Pradesh

श्री रमेश बिन्द (भदोही): मेरे लोक सभा क्षेत्र भदोही के अंतर्गत भदोही और मिर्ज़ापुर जिला आता है जो कालीन और अन्य उद्योगों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और इनका निर्यात विश्व के कई देशों को किया जाता है। ट्रेन नंबर 12559/12560 शिवगंगा एक्सप्रेस वर्तमान में बनारस से दिल्ली के बीच चलती है और सिर्फ कानपुर अथवा प्रयागराज स्टेशन पर इसका ठहराव है। भदोही जिले के अंतर्गत आने वाले ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेन जैसे चौरी चौरा एक्सप्रेस और स्वतंत्र

^{*} Treated as laid on the Table.

सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव है और विगत कई वर्षों से यह मांग है कि शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप मिर्ज़ापुर और भदोही जिले के व्यापारी, छात्र और उपचार के लिए यात्रा करने वाले मरीज़ों को राहत मिलेगी और मेरे लोक सभा क्षेत्र भदोही के आर्थिक विकास और कालीन उद्योग को और भी गति मिलेगी। मेरा सरकार और रेल मंत्रालय से आग्रह है कि शिवगंगा एक्सप्रेस का ठहराव ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की मांग को तत्काल स्वीकृति दी जाए जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र के निवासियों को उद्योग, शिक्षा या उपचार के लिए यात्रा करना आसान होगा और पूर्वांचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने के अतिरिक्त रोज़गार भी उत्पन्न होगें।

(xv) Regarding introduction of air conditioned rail ambulance

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में एम्बुलेंस के अभाव के कारण बहुत सारे मरीज़ों की मृत्यु हुई और NCRB के अनुसार प्रतिदिन 24012 लोग समय पर सहायता ना मिलने से अपनी जान गवा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का लक्ष्य रखा है जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है लेकिन आज भी ग्रामीण, किसान और गरीब परिवारों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की आवशयकता पड़ती है और कई बार जब बीमारी गंभीर हो तो उसको उपचार हेतु अन्य शहरों में भी जाना पड़ता है। रेलवे ने 2017 में air conditioned rail ambulance का प्रावधान किया था जिसमे एक समय पर 50 मरीज़ यात्रा कर सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार किसानों के हित के लिए किसान रेल का संचालन हो रहा है उस प्रकार रेल एम्बुलेंस का प्रावधान हर रेलवे जोन में किया जाए जिससे मरीज़ों को आपातकालीन स्थिति में गैर सरकारी एम्बुलेंस पर निर्भर ना होना पड़े जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान होता है और बहुत सारे परिवार इसके परिणामस्वरूप कर्ज़ में डूब जाते हैं। रेलवे एम्बुलेंस के संचालन से ग्रामीण और गरीब परिवार के मरीज़ रेल के माध्यम से उपचार सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

(xvi) Regarding setting up of an airport at Chengannur in Mavelikkara Parliamentary Constituency

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kerala holds an important position in the nation's economy as the largest recipient of external remittance, home to the largest diaspora and an important tourist destination. The central Travancore region composed of Kottayam, Pathanamthitta, Idukki and alappuzha is of immense significance as the hub of NRIs and Expats both in terms of numbers and movement and world renowned tourist destinations. However, a long standing demand of establishing an international airport for serving central travancore region, has been left unfulfilled. The demand for an airport at Chengannur is rising now as Chengannur is an ideal location for creating a Hub and Spoke network of access based development of the entire central Travancore region and to facilitate international travel and tourism. I request the government to depute an expert committee to conduct a detailed feasibility study and technical review of an airport project at Chengannur that falls within my Lok Sabha Constituency Mavelikkara.

(xvii) Regarding construction of a bridge over river Bhavani in Palakkad district, Kerala

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The death of tribal infant children is going on unabated in Attappadi Taluk in Palakkad district. Again on 14.7.2022, death of an infant child of a couple of Murugala ooru of this taluk took place. Tribals of this taluk have to walk many kilometres to avail of medical facilities. There are no basic facilities available to the tribal hamlets falling in the forest areas and no vehicle can reach these hamlets in case of emergency. There is an urgent need to construct a bridge over river Bhavani and road leading to the proposed bridge, so that these people could avail medical treatment. I have raised issues concerning the plight of these tribal people many times in this august House, including a demand to set up a development authority to take care of this tribal people. Therefore, I urge upon the Government to take all measures to prevent the death of children in Attappadi taluk urgently by creating all necessary basic facilities which can be possible by setting up a development authority.

(xviii) Regarding plight of traditional indian fishermen

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Millions of Indian traditional fishers are facing a threat of extinction due to many reasons. The natural calamities and climate change have already posed a huge challenge in front of them. And also the lives and livelihoods of traditional marine fishers are in serious trouble because of the policies of Government. The recent Geneva Ministerial Summit of WTO decided to drop all subsidies for fishing and allied activities which will harm our fisheries severely. India was expected to protest against this injustice done by WTO, instead it agreed to it. This will wash out our fishers from our coasts. The excessive price hike of Kerosene became a choking issue among fishers. In Kerala itself, the price of Kerosene jumped to Rs. 102. The Kerosene quota for fishers has been cut down to 129 litres per month from 450 litre per month. And the state quota has also been cut down by the Union government. This is outrageous and condemnable. The GOI must be awakened to these issues impacting one of the most segregated communities in the country. Our fishers are in a desperate need of help to survive.

(xix) Need to operate a regular reserved train between Coimbatore/Mettupalayam and South Tamil Nadu

SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): Lord Murugan temple in Palani is one of the most visited pilgrimage centres in India. Millions of pilgrims every year from other countries and from India (especially from Tamil Nadu & Kerala) visit Palani temple. Palani serves as one of the nearest rail head for world famous tourist hill destination "Kodaikanal". Also, Dindigul is the one of municipal corporations of Tamil Nadu which has various industries and educational institutions. Oddanchatram is a commercial town in Dindigul constituency and has one of the largest vegetable markets in India. I would like to highlight that there is no regular reserved train operating at present between Coimbatore / Mettupalayam and South Tamil Nadu through the shortest rail route (via. Palani). The service of trains is going to end by this week (1st July, 2022). I request the Hon'ble Railway Minister for making the services of train permanent in the interest of the general public.

(xx) Regarding RINL tender relating to coke oven batteries

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): RINL had turnaround last year and broke all previous records, be it production, sales, export, etc., and earned a profit of 835 crores and gross margin of 3,575 crores which was best ever since setting up of the plant. So, instead of encouraging it to do better, it seems, GOI is pulling it down in every possible way. Firstly, RINL is not being supplied coal due to Railways not giving rakes for coal transportation. Secondly, GOI has, on 25-06-2022, issued tender inviting interested parties to come and take over 2 coke oven batteries on contract basis. Batteries play an important role in steel production and handing over batteries under the garb of comprehensive battery maintenance is nothing but privatization of RINL which is not acceptable to workers and people of AP since more than 500 workers are working in each coke oven batteries.

Hence, I demand to immediately withdraw tender issued by Government.

(xxi) Regarding promoting export of agricultural products

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): With only 2.4% of the world's land and 4% of its water resources, India supports 17.84% of the world's population and 15% of the livestock population. It is encouraging that India's role in global agricultural exports is steadily increasing. According to World Trade Organization trade data, India's agricultural and allied exports during 2019-20 were Rs. 2.52 lakh Crores. India's share of global agricultural exports has increased from 1% a few years ago to 3.1% in 2019. Recent growth rates show that agri-food production is increasing faster than domestic demand, and the volume of surplus for export is increasing rapidly. This provides scope and opportunity for capturing overseas markets in order to earn money. India needs a direct export channel for farmers to revitalize the entire value chain, from export-oriented farm production and processing to transportation, infrastructure, and market access. A framework for sustainable agriculture, on the one hand, and a viable agriculture export policy on the other hand have a mutually beneficial relationship.

Hence, it is necessary to develop a policy that will directly benefit the farmers by providing them with vital opportunities to export their products overseas.

(xxii) Need to develop sports infrastructure and facilities under 'Khelo India Yojana' in Goplaganj district, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं केंद्र प्रायोजित "खेलो इंडिया योजना" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिससे जनता, इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से खेल-कृद की क्षमता का उपयोग कर सके। खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल के बुनियादी ढांचे की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और उन्नयन के माध्यम से खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना; खेल के मैदान का विकास करना; सामुदायिक कोचिंग विकास; सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना; ग्रामीण और स्वदेशी खेलों के साथ-साथ स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एक मजबूत खेल प्रतियोगिता संरचना की स्थापना, दिव्यांगजनों के लिए खेल तथा महिला खेल और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन करना शामिल है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के गोपालगंज जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और अधिक महत्व वाले क्षेत्रों के निवासियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करके ग्रामीण विकास लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है। " खेलो इंडिया योजना" से खेल के बुनियादी ढांचे और खेल के मैदान की सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से निश्चित रूप से बिहार के जिला गोपालगंज में ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों का विकास होगा। मैं माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बिहार के गोपालगंज जिला को खेलो इंडिया योजना के तहत शामिल किया जाए ताकि खेलकूद की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल के ब्नियादी ढांचे और खेल के मैदानों की व्यवस्था की जा सके और लोगो को खेल गतिविधियां में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

(xxiii) Regarding payment of arrears of honorarium to Madrasa teachers and also increase the amount of honorarium being paid to them

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): उत्तर प्रदेश के मदरसों में कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को Scheme for Providing Education to Madrasas/Minorities (SPEMM) योजना के अन्तर्गत सरकार ने 2022 में कुछ महीनों के लिए वेतन का भुगतान किया है, लेकिन 2017 से 2021 तक उनके लंबित बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षकों को सालों से मानदेय वेतन नहीं मिलने की वजह से इन शिक्षकों में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। मदरसा शिक्षकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है लगातार हो रही मदरसा आधुनिकीकरण ने मदरसा शिक्षकों को आघात पहुँचाया है। सरकार की तरफ से अभी तक न तो बकाया मानदेय दिया गया है और न ही शासन-प्रशासन का नुमाइंदा कोई सुध ले रहा है। वेतन नहीं मिलने से मदरसा शिक्षक भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जिससे प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का नारा बेमानी साबित हो रही है।

सरकार से मेरी मांग है की इन शिक्षकों का केंद्र व प्रदेश सरकार पर अब तक कितना बकाया राशि है ये स्पष्ट करें एवं तत्काल केंद्र व प्रदेश पर लंबित इन का मानदेय जारी कराया जाय, महंगाई को देखते हुए मानदेय बढ़ाया जाय अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इन को भी पूरा मानदेय प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान किया जाय।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، اتر پردیش کے مدرسوں میں کام کرنے والے مدرسہ آدھونیکی کرن ٹیچرس کو Scheme for Providing میں کام کرنے والے مدرسہ آدھونیکی کرن ٹیچرس کو Education to Madrasas / Minorities (SPEMM)

2022 میں کچھ مہینوں کے لئے تنخواہ کی ادائیگی کی ہے، لیکن 2017 سے 2021 تک انکے لمبِت بقایہ کا بھگتان نہیں کیا گیا ہے۔

ٹیچرس کو کئی سالوں سے ماندے تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے ان ٹیچرس میں مرکزی و صوبائی سرکاروں کے خلاف بہت غصہ ہے۔ مدرسے کے ٹیچرس میں مرکزی و صوبائی سرکاروں کے خلاف بہت غصہ ہے۔ مدرسے کے ٹیچرس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ ماندے نہ ملنے کی وجہ سے لگاتار ہو رہی ٹیچرس کی موتوں نے ٹیچرس کو گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ سرکار کی طرف سے ابھی تک نہ تو بقایہ ماندئے دیا گیا ہے اور نہ ہی شاسن ، پرشاسن کا کوئی نمائدہ کوئی سندھ لے رہا ہے۔ تنخواہ نہ ملنے کی ٹیچرس بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ جس سے وزیرِ اعظم کے سب کا ساتھ سب بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ جس سے وزیرِ اعظم کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نارہ ہے معنیٰ ثابت ہو رہے ہے۔

سرکار سے میری مانگ ہے کہ ان ٹیچرس کا مرکزی و صوبائی سرکاروں پر کتنا بقایہ ہے واضح کریں اور مرکزی و صوبائی سرکاریں جلد سے جلد ان کا بقایہ جاری کرائیں، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ماندئے بڑھایا جائے دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح ان کو بھی پرا ماندئے ہر مہینے دئے جانے کا پراودھان کیا جائے۔ شکریہ..]

(xxiv) Regarding merger of schools in Andhra Pradesh

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): AP government is playing with the future of our children by merging schools and reducing the number of teacher posts. Classes 1, 2 are being merged with anganwadis. Classes 3, 4, 5 are being integrated with high schools. Parents don't know if the school in which their child is studying in will exist tomorrow or not, leading to uncertainty about their child's future. Pupil teacher ratio will be worsened, defeating the 'very concept of quality education'. AP Govt. is still going ahead with the merger despite protests by Parents and students. AP is using NEP as an excuse for all this mess. However, disintegration of primary schools has not been recommended by NEP or RTE. AP Govt. is allegedly lying to the people. Hence, I request the Centre to take action regarding the act of AP state to stop this mindless merger of schools, which is destroying the future of our students.

(xxv) Regarding sanctioning of a Central Agriculture University in Tamil Nadu

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Tamil Nadu is one of the key food-producing states in the country with nearly 70% of the population engaged in agriculture and allied activities. Also, Tamil Nadu holds a significant position with respect to the output of agricultural produce. Hence, crucial initiatives and interventions are needed to develop sustainable farming systems for improving productivity and profitability in agriculture and allied sectors. Also, there is a need to train farmers in modern and advanced agricultural technology.

To promote excellent strategic & anticipatory research in the field of agriculture, the establishment of an institution of higher learning is vital. Such an institute will serve as an important link in the chain for converting agriculture and allied vocations, into profitable enterprises, and offering food and nutritional security for our nation.

Hence, I urge the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers welfare, to sanction a Central Agriculture University in Tamil Nadu, that will serve as a centre of excellence in teaching, research and extension education in the field of agriculture and allied sectors.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

14.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)

16.0½ hrs

At this stage, Adv. Dean Kuriakose, Dr. DNV Senthilkumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. CHAIRPERSON: Please have your seats. 'Zero Hour' is a very important thing we take up in the Parliament. Let the Members ask whatever is important.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will give you a chance. Please have a seat.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Deepak Baij.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Pradeep Kumar Singh.

... (Interruptions)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अरिया): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आज जिस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं, वह निश्चित ही चिंतनीय व विचारणीय है।...(व्यवधान) महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से मजबूती देने का काम किया है, वह प्रशंसनीय है।...(व्यवधान) आज पंचायत स्तर पर चारों तरफ हो रहे विकास से ग्रामीणों में खुशी है, परंतु कुछ

गंभीर मसले, विषय ऐसे हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना अति आवश्यक है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not disrupt the proceedings of the House. Please be seated.

... (Interruptions)

श्री प्रदीप कुमार सिंह: महोदय, साल 2004 में बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ, अनुच्छेद की धारा 33 के अनुसार दलपित के अधीन ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था।...(व्यवधान) रक्षा दल का गठन पंचायत स्तर पर किया गया।

किसी तरह की आकिस्मिक घटना, आगलगी, महामारी, चोरी, डकैती, विधान सभा या लोक सभा चुनाव हो, उसमें भी उनसे काम लिया जाता है। विगत कुछ वर्ष और कोरोना में भी उनसे काम लिया गया।... (व्यवधान)

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक भीषण समस्या जल संकट, जो मानव जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सभापित महोदय, आज संपूर्ण बिहार और खासकर मिथिला का क्षेत्र भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। कभी अत्यिधक बाढ़ तो कभी सुखाड़, शायद इस क्षेत्र के लोगों के लिए नियित ही बन चुकी है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मिथिला क्षेत्र की पहचान को इस पंक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है

– पग-पग पोखर माछ मखान अर्थात इस क्षेत्र में पोखर और तालाब की बहुलता थी जिसके कारण
मछली और मखाना का उत्पादन अत्यधिक होता था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज वे पोखर अतिक्रमित होने के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं और जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।...(व्यवधान)

सभापित महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में जल संरक्षण हेतु प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 75 तालाब खुदवाने का जो निर्णय लिया है, वह सराहनीय कदम है और खासकर मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Dharambir Singh.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohanbhai Kundariya.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Arjunlal Meena.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Beesetti Venkata Satyavathi.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairperson Sir, in a move to capitalize on its marine reserves, the State Government of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has decided to set up new fishing harbours in a fast track mode. ... (*Interruptions*). The proposed sites for the same include Juvvaladinne, Nizampatnam, Machilipatnam, Uppada, Bundagatlapalem, Pudimadaka, in my constituency Kothapatnam, and Biyyaputippa among others. ... (*Interruptions*).

With a proposed expenditure of about Rs. 400 crore on each of the fishing harbour, this move is expected to transform the lives of fishermen in the State. New harbours in this sense will help anchor about 10,000 mechanised boats. ... (*Interruptions*). Further it will help the fishermen in the State to catch

about 3,00,000 metric tonnes of fish annually due to which our one lakh fishermen will get livelihood. ... (*Interruptions*)

Therefore, hon. Chairperson Sir, in order to augment the resources of the State of Andhra Pradesh, which has been bereft of its former resources post the re-organization of the State in 2014, it is the need of the hour for the Union Government to provide financial support to the State in the construction of such fishing harbours. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back and be seated.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your fellow Members have to raise important issues. Let them speak.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting everybody to go because there are very important issues to be taken up.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again tomorrow, 21st July, 2022 at 11 AM.

16.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 21, 2022 / Ashadha 30, 1944 (Saka)

<u>INTERNET</u>

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)